**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1103**

**23 मार्च, 2012 के लिए उत्‍तरार्थ**

**विषय: विदर्भ में किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या किया जाना**

**1103. श्री प्रकाश जावडेकर:**

**क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) विदर्भ क्षेत्र में वर्ष 2005 से अब तक कितने किसानों ने आत्‍महत्‍या की है;

(ख) तत्‍संबंधी वर्ष-वार ब्‍यौरा कया है; और

(ग) आत्‍महत्‍या की घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि मंत्री( श्री शरद पवार)**

**(क) तथा (ख):** महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पुनर्वास पैकेज में शामिल विदर्भ क्षेत्र के चिन्‍हित जिलों में वर्ष 2005 से कृषि कारणों की वजह से किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या की संख्‍या 276 (2005), 565 (2006), 350 (2007), 340 (2008), 273 (2009), 275 (2010) और 209 (2011) है।

**(ग):** किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या किए जाने को रोकने, उनकी स्‍थिति में सतत आधार पर सुधार करने तथा कृषि क्षेत्र को पुन: सक्रिय करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्‍नलिखित शामिल हैं:-

1. आन्‍ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं महाराष्‍ट्र में 31 जिलों को कवर करते हुए पुनर्वास पैकेज का कार्यान्‍वयन जिसके तहत 30 जून, 2011 तक 19910.70 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्‍त की गई है ।
2. कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 का कार्यान्‍वयन जिसके तहत अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 65318.33 करोड़ रुपये की ऋण माफी/राहत से लगभग 3.69 करोड़ किसान लाभान्‍वित हुए ।
3. मार्च, 2011 तक कृषि क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह 468291.28 करोड़ रुपये तक बढ़ाना । 2011-12 के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्‍य 475000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है जिसमें से नवम्‍बर, 2011 तक 294023 करोड़ रुपये की उपलब्‍धि हुई ।
4. किसानों को ऋण प्रवाह में सरलता लाने एवं वित्‍तीय अन्‍तर्वेशन बढ़ाने के लिए समयबद्ध तरीके से सभी पात्र एवं इच्‍छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्‍ध कराना । अक्‍तूबर, 2011 तक 10.78 करोड़ केसीसी जारी किए गए हैं ।
5. 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण की समय पर अदायगी के लिए ब्‍याज दर में छूट उपलब्‍ध कराना जिससे समय पर फसल ऋण देने वाले किसानों के लिए ब्‍याज की प्रभावी दर 4% प्रति वर्ष तक कम होगी ।
6. फसल पूर्व ब्‍याज दर पर छूट का यह लाभ अब केसीसी धारक छोटे एवं सीमान्‍त किसानों को भी भाण्‍डागार में उनके उत्‍पाद रखने के लिए परक्राम्‍य भाण्‍डागार रसीद के विरुद्ध फसलोपरान्‍त आगे 6 महीने की अवधि के लिए उसी दर पर जैसी कि फसल ऋण के लिए है, उपलब्‍ध है ।
7. लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रत्‍येक वर्ष चिन्‍हित कृषि जिन्‍सों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) की घोषणा । मुख्‍य कृषि जिन्‍सों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर्याप्‍त रुप से बढ़ाया गया है उदाहरणार्थ 2004-05 से 2011-12 के दौरान मूंगफली के मामले में एमएसपी 80 % से दलहन (मूंग) के लिए 148 % तक बढ़ा है ।

सरकार द्वारा किए गए अन्‍य उपायों में अन्‍य बातों के साथ-साथ विभिन्‍न योजनाओं जैसे राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन, राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई मिशन, पनधारा प्रबंधन, मृदा स्‍वास्‍थ्‍य एवं उर्वरता प्रबंधन इत्‍यादि के कार्यान्‍वयन के जरिए कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को पर्याप्‍त रुप से बढ़ाना शामिल है ।

**-----------**